श्री सभापति: आपकी मुश्किलात बहुत है, पर मेरी भी मुश्किल बहुत है।

श्री शिवराज वी.पाटिल: हां, तो आपकी मुश्किल और मेरी मुश्किल को समझकर, इसके बारे में मालूमात लेकर मैं सदन को दे दूंगा, मगर कहीं किसी का हाथ टूट जाए, कहीं कत्ल कर दिया जाए, स्टेट की हर चीज यहां पर आ गई, तो मैं तो इन्हीं में ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह स्टेट का प्रश्न नहीं है, थोड़ा इन atmposphere एटमोस्फेयर का प्रश्न है।

श्री शिवराज वी.पाटिल: मैं मालूमता लेकर सदन को बता दूंगा।

श्री सभापति: ठीक है। अब कॉलिंग अटेंशन ....श्री एस.एस.अहलुवालिया...

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Grave situation arising out of the prolonged violence prevailing in tribal dominated areas in Assam

श्री एस.एस.अहलुवालिया (झारखंड): सभापति महोदय, असम में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में काफी लंबे समय से चली आ रही हिंसा, जिसमें जान-माल की हानि हुई है, की गंभीर स्थिति के संबंध में गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRi SHIVRAJ V. PATIL): Mr. Chairman, Sir, the overall security situation in the North East has shown signs of improvement not only in terms of declining levels of violence but also through growing public revulsion against mindless acts of terrorism. There have been increasing instances of public protests against highhandedness by militant cadres and the people are now forthcoming to speak against the militants.

† Original notice of the Question was aceived in Hindi.

Karbi Anglong district in Assam, along with neighbouring North Cachar Hills district are two districts, which have majority of hill tribes in Assam. These districts have population of dominants tribes, namely, Karbis in Karbi Anglong and Dimasas in N.C. Hills. In both the districts, other tribes like Kukis, Hmars and Khasis are also settled in Sizeable numbers. Both the districts are covered under Sixth Schedule to the Constitution of India and enjoy a large degree of autonomy. There have been tensions and rivalries between different tribes. During October 2003 to June 2004, there were clashes in Karbi Anglong between Karbis and Kukis over ginger cultivation. Clashes this year started with killing of three Dimasas in Diphu Policy Station area on 26th September, 2005. The situation took a communal turn and five Karbis were killed on 2nd October, 2005. There were incidents like attacks and burning of houses of the two communities. In a major violent incident, on 17th October, 2005, forty Karbis were taken out of a bus and brutally killed.

A large number of persons, who took shelter in the relief camps, have returned to their native places. At present (as on 13th November, 2005) about 19,500 people are in relief camps in Karbi Anglong, Nagaon and N.C. Hills districts. Rehabilitation measures undertaken by the State include sanction of Rs. 3 lakhs as *ex-gratia* grant to the next of the kin of the victims; providing Gratuitous Relief (GR) to the affected families; and, rehabilitation assistance for construction of houses. The Government of India is helping the Government of Assam for granting *ex-gratia* to the deceased family, providing GR and rehabilitation grant to the affected families.

The violent activities in Karbi Anglong suspected to have been abetted by the militant groups of the particular tribes for area domination.

Shri Sriprakash Jaiswal, the Minister of State, in the Ministry of Home Affairs, visited Karbi Anglong on 20th October, 2005, and met the people affected by the violence. The Secretary (Border management), in the Ministry of Home Affairs, also visited Diphu at the same time and reviewed the security situation with the Chief Secretary, GDP and other security forces. A senior officer from the Ministry, again, visited Diphu on 4th November, 2005, and reviewed the security situation and rehabilitation process. Additional Central Police Forces and Army were also deployed to help the State Government to control the situation.

The situation is being closely monitored. Additional Central Police Forces and Army units continued to be deployed in the area.

श्री एस.एस.अहलुवालिया: सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय ने मेरे ध्यानार्कषण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए बताया है कि काबीज और कुकीज की जो लडाई है, खासकर यह अदरक की खेती को लेकर हो रही है। महोदय, मैं जरा इस इलाके के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा कि नार्थ-ईस्ट रीजन के इस इलाके के लिए, जब देश आजाद हुआ तो एक सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलई बनाई गई थी। इसका 1947 में नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर असम के बारे में एक सब कमेटी का नाम दिया गया था। इसमें खासकर कार्बी आंगलांग के बारे में, ट्राइबल और नान ट्राइबल के बारे में विचार करना था। विचार करते वक्त कार्बीज ने मांग की थी कि हमें एक सैप्रेट डिस्ट्रिक्ट बनाने दिया जाए, जहां पर हमारा बाहुल्य हो। 18 मई, 1947 को उनके मैमोरेंडम पर विचार करते हुए अंततः 23: जून, 1952 को कार्बी आंगलांग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काऊंसिल बनाया गया। महोदय, आज जो परिस्थिति है उसके अनुसार यहां पर दो संस्थाएं हैं, जिनके बारे में वहां कि इंटेलीजेंस और असम की पुलिस कहती है कि DHD और UPDS अर्थात् दीमा हालोंग दावत और युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रटिक सोलिडेरिटी,...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे.कुरियन) पीठासीन हुए)

DHD और UPDS, में दोनों आपसे में लड़ रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए एक अगस्त, 2002 को, इन दोनों संस्थाओं के बीच में एक सीजफायर की घोषणा की गई। सरकार किसी की भी रही हो, पर कभी-कभी आश्चर्य होता है कि दो ग्रुपों में लड़ाई हो रही है। या दो जातियों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो ट्राईबल ग्रुपों के बीच में लड़ाई हो रही है और सीजफायर की घोषणा होती है। अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही हो, तो सीजफायर का रूल है, उसके पीछे रियलिटी है, उसको मद्देनजर रखकर सीजफायर डिक्लेयर होती है, लेकिन एक ही जिले के अंदर दो वार्निंग ग्रुप्स हैं, उनके बीच में सीजफायर डिक्लेयर होती है, यह सुनकर जरा अटपटा लगता है। मेरे ख्याल से आज तक सीजफायर के ग्राउण्ड रुल्स नहीं बने हैं। ऐसे ही इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में National Democratic Front of Bodoland यानी NDFB के साथ mid 2005 में सीजफायर डिक्लेयर की गई थी, भारत सरकार के कहने पर की गई थी, ULFA के साथ भी सीजफायर डिक्लेयर की गई थी, किंतु बात ऐसी हो रही है कि जब सीज़फायर की जाती है, तो दोनों पक्षों को disarm करना चाहिए, न तो DHD disarm हुई और न UPS disarm हुई। इनकी आर्गनाइजेशन के जो मिलिटेंट लोग थे, उनको निर्धारित कैंपों में रखा गया और उस कैंप की सुरक्षा पुलिस के पास है।

महोदय, वर्ष 2002 में जब यह काम हुआ था, तब भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं, इसलिए सीजफायर डिक्लेयर की गयी थी, किंतु ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती गई। अब चिंता का विषय यह हो गया है कि 26 सितंबर को जब हल्ला हुआ, मैं खुद गया था, श्रीप्रकाश जायसवाल जी वहां 20 तारीख को पहुंचे, मैं 18 और 19 तारीख को वहीं था और मैंने उस इलाके का दौरा किया। उस इलाके का दौरा करते हुए मैं उन रिलीफ कैंपों में भी गया, जहां पर लोगों ने refuge लिया हुआ है। ऐसे 54 कैंप हैं, जहां पर करीब 55,000 लोग रह रहे हैं। वे एन.सी. हिल्स में भी है, कार्बी आंगलांग में भी है, हुजाई में भी है, नगांव के पास हुजाई में भी है, क्योंकि डाऊन कार्बी आंगलांग के इलाके से भागकर वे गए हैं। मैंने उनके हालात देखे उनकी घबराहट देखी उनका डर देखा और उनसे बात की। यह ठीक उसके बाद की बात है, जब बस से उतारकर लोगों को सरेआम काटा गया था। पुलिस ने कहा कि जिन्होंने अटैक किया था, वे नकाबपोश थे, उन्होंने मिलिट्री ड्रेस पहन रखी थी और उनके पास सोफिसटिकेटेड आर्म्स थे, वीपन थे, पर अगर मृत शरीरों को देखा जाए, अगर उनकी फोटोग्राफ्स देखी जाएं, या उनकी पहचान बताई जाए, तो उनकी गरदनें काटी हुई थीं, उनकी सरेआम किसी धारदार हथियार से हत्या की गई थी।

महोदय, यह अपने आप में बड़ा अटपटा लगता है कि जिसके पास एके-56 हो, वह भुजाली चालकर दूसरे की गरदन क्यों काटेगा? गरदन काटने में तो उसको समय लगेगा और एके-56 का trigger दबाकर वह कम समय में ज्यादा आदमियों को मार सकता है। क्या वे आंतकवादी थे या कुछ ऐसे लोग थे? वहां बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या कारण है, आखिर हत्या क्यों हुई? वहां जो दिमासा ट्राईब है, वह केवल 3 परसेंट है, कार्बी वहां पर मैजोरिटी में है। कुछ लोगों का कहना था कि दमासा ने, कार्बियों की हत्या की, इसलिए उसका रियेक्शन हुआ। पहले जो 3 मारे गए, वे दिमासा थे। उसके बाद जो एक-दो गांवों से मारना शुरू किया और गांव जलाने शुरू किए, इसके कारण लोगों में भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घरों से बेघर हो गए।

महोदय, दिमासा के जो प्रमुख लोग हैं और कार्बीज के जो प्रमुख लोग हैं, मैं दोनों से मिला। वे दिल्ली आकर आपसे भी मिले, यहां प्रमुख नेताओं से भी मिले, राष्ट्रपति से भी मिले और प्रमुख पार्टियों के नेताओं से भी मिले। सब जगह मिल कर उन्होंने सारा विश्लेषण दिया और दोनों ने मिलकर मेमोरेंडम दिया कि यह काम न तो दिमासा का है और न ही कर्बीज का है। यह तीसरी शक्ति कौन है, इसे कौन कर रहा है, इसका पता लगाना जरूरी है। इसलिए वे बार बार मांग कर रहे हैं, कुछ संस्थाएं भी मांग कर रही हैं कि इसमें सीबीआई की जांच शुरू हो। (**समय की घंटी**) कुछ संस्थाओं ने यह मांग की है कि वहां के हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी इन्क्वायरी हो। महोदय, जब तक इसकी इन्क्वायरी नहीं होती तब तक यह पता नहीं लेगा कि यह तीसरी शक्ति

कौन है। कुछ लोगों की यह शंका है कि ग्रेटर नागालिम का जो नक्शा है, उस नक्शें में कार्बी आंगलोंग को नागालैंड का हिस्सा बताया गया है। उन्हें डर है कि थंगकुल ग्रुप के एनएससीएन के लोग भी इसमें इंवाल्व हो सकते हैं। किन्तु जब तक किसी इन्क्वायरी की जांच के माध्यम से यह तथ्य बाहर न आए, सब लोग अंधेरे में हैं। सब लोग यही सोच रहे हैं। मैंने तो कई ऐसे कैम्प्स देखे, जहां पर दिमासा के कैम्प और कर्बीज के कैम्प अगल बगल में है और आपस में भी कोई भेदभाव भी नहीं है। दिफू शहर के एकदम बीच दिमासा का एक कैम्प है, जहां चारों तरफ कर्बीज का घेरा है, वह चल रहा है। वे थोड़े आंतिकत थे, उनसे मिल कर हमने कहा कि हम पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन, गवर्नर से और होम मिनिस्टर से बात करेंगे कि आपको सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है।

महोदय, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि तीन लाख रुपये कंपेसेशन की घोषणा की गई है, सैंक्शन किया गया है। मुझे कल तक की खबर है कि यह कंपेसेशन अभी तक उन्हें पे नहीं की गई है। इसकी पेमेंट नहीं हुई है। यह चिन्हित है कि कौन लोग मारे गए हैं और उनके परिवार वाले किस कैम्प में रह रहे हैं। अभी तक उन्हें कंपेंसेशन नहीं दिया गया है। वे 54 कैम्प्स चिन्हित है, जहां पर इस खंड में बुरा हाल है। ऊनके पास न तो नीचे बिछाने के लिए कोई कम्बल है, न ओढ़ने के लिए ही कम्बल है और न मच्छरदानियां हैं, क्योंकि वहां मच्छर बहुत होते हैं। बच्चे बीमार है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था में उन्हें जो चावल, दाल, आलू या प्याज दिए गए, तो वहां खाने के लिए बरतन नहीं है। मैं यह सारा हाल देख कर आया। एनजीओज़, दूसरी संस्थाओं और दूसरी पार्टियों ने वहां जाकर बांटा, अभी उसकी खानापूरी हुई है कि नहीं। जो प्रेगनेंट वुमेन वहां बैठी हैं, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां इस 55 हजार में गर्भवती महिलाएं सैकड़ों की संख्या में हैं। वे किस तरह से जंगल में भागकर कर अपने प्राण की रक्षा करते हुए अपने गर्भ के बच्चे की रक्षा करेंगी। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे.कुरियन) : आप जल्दी खत्म कीजिए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, it is a very serious matter of the North-East. Every subject gets importance here. But it is a far-flung area from Delhi. Let the grievances of that area be ventilated in this House.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे.कुरियन) : ठीक है, ठीक है। आप बोलिए। लेकिन आप जल्दी कंक्लूड कीजिए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am concluding. इन सारी चीजों की व्यवस्था की जरूरत है। मैं जिस दिन गया था, उस कैम्प में मुझे देखने से ही पता लगता था कि जिस तरह

से वहां पर डाक्टर्स और नर्सेज को बिठाया गया, उनसे पूछा गया कि आपने सब का ब्लड चेक किया कि नहीं, सबको टेस्ट किया कि नहीं, सबके मेडिकल कार्ड बन गए कि नहीं। वहां नए-नए टेबल लगाए गये थे वहां नए-नए बेंच लगाए गए थे, लोग नई-नई वर्दियां पहन कर खड़े थे, वे सुविधाएं वहां उपलब्ध थीं, क्योंकि शायद वहां उस दिन गवर्नर साहब को भी आना था और दूसरे दिन हमारे गृह मंत्री जी को भी वहां पहुंचना था। उनके लिए यह तैयारी की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, यह मालूम नहीं।

इसी की आड़ में वहां कंवर्जन का भी काम शुरू हो गया है। मैंने वहां देखा कि बहुत सारे विक्टिम लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं। उनके गले में नए-नए क्रॉस के चिन्हं पहनाए गए हैं। मैंने उन आदिवासियों से पूछा कि यह आपने कब पहना, कब से पहन रहे हो, किस ने पहनाया? उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार वालों की आत्मा को शांति मिलेगी, हमतो कोई पूजा-पाठ करा नहीं सकते, हम तो घर छोड़कर भाग आए हैं क्योंकि हमारा घर जंगल सब जला दिया गया है। हम तो जंगल से भागते-भागते यहां आए हैं। उन्होंने यह पहना दिया है और ऐसे प्रेयर करने के लिए बताया है। इस तरह यह चल रहा है। तो वहां रिलीफ के नाम पर इस तरह की मदद के साथ conversion का काम भी हो और वहां पर normalcy लाने की कोई कोशिश न हो तो क्या कहेंगे? वहां मुख्य मंत्री गए और जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि मुख्य मंत्री महोदय, इतने लोग मारे गए हैं, आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जंगल में लोग नहीं मरेगा तो कहां मरेगा? यह तरुण गोगई जी का जवाब था जिसे असम के सारे अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर छापा। वहां के गृह मंत्री गए, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहे। वे एक रात बिताते, वहां के लोगों से बात करते, वहां के लोगों की तकलीफों को जानते और उन को तकलीफों से मुक्त कराने के लिए रिलीफ मुहैय्या कराते। मगर वहां तरुण गोगई सरकार के गृह मंत्री गए और 10 मिनट में वहां से चले आए। महोदय, मेरी मांग है कि वहां पर डी.एच.डी. और यू.पी.डी.एस. जिस को सीजफायर डिक्लेयर हुआ है, उन को पहले disarm किया जाए। वे आप के द्वारा चलाये कैंपों में रह रहे हैं। उन को disarm किया जाए और उनके साथ, अगर "उल्फा" के साथ बात करने के लिए जो उल्फा और भारत सरकार के बीच में पीस कंसल्टेटिव ग्रुप जो बनाया गया है, इन के बीच भी वह ग्रुप बनाकर इन से सलाह करें कि आखिर उस इलाके में क्या हो रहा है? साथ ही आप ने जिस इलाके को भारत के संविधान के मिलते मिलते छठवीं अनुसूची में लाकर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया था और यह अधिकार प्राप्त किया था कि यहां पर हिल एरिया के ट्रायबल्स रहेंगे, आज वे सुरक्षित कैसे रहें, आपस में अंतर्द्वंद न हो उस को बंद करने का रास्ता ढूंढा जाए। अगर ये नागालैंड के नक्शे में दर्शाया जाना है और आतंकवादी, उग्रवादी और अलगावबादी ताकतों का हाथ है तो उस पर कार्यवाही हो। महोदय, हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा इस की इंक्वायरी किया जाना बहुत जरूरी है कि आखिर यह तीसरी शक्ति कौन

है? यह जानना बहुत जरूरी है। यह जब तक वहां के लोगों को पता नहीं लगेगा तब तक शायद वे कैंप से अपने गांव वापिस नहीं जाएंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please try to conclude.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am putting forth my demand. महोदय वहां पर जब तक normalcy restore नहीं होगी तब तक लोग गांव वापिस नहीं जाएंगे। महोदय, जैसा कि मैंने compensation के बारे में कहा कि यह वहां किसी को नहीं दिया गया है, वह तुरंत उपलब्ध कराया जाए।

महोदय, सीजफायर के बारे में ग्राउंड रूल्स जब तक नहीं बनते और नॉर्थ ईस्ट एरिया में जितने भी ट्रायबल ग्रुप हैं या इस तह के आउटफिट्स हैं जिन के साथ भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीजफायर डिक्लेयर किया हुआ है और उन को सारी चीजें मुहैय्या की है, लेकिन उन को disarm नहीं किया है, तो उन के साथ बातचीत शुरू हो। उसी के साथ मैं चाहता हूं कि Natioanl Democratic Front of Bodoland के साथ भी वैसी ही चर्चा शुरू होनी चाहिए। उन के साथ भी आप ने 2005 में सीजफायर किया है और उन के साथ चर्चा में नहीं बैठे, कोई कमेटी नहीं बनायी कि वे चर्चा किस के साथ करें। महोदय, चर्चा सिर्फ "उल्फा" के साथ चल रही है और national security Adviser के साथ चल रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आप सीजफायर पर क्या करेंगे? दूसरे वहां जिंजर की खेती को लेकर जो गड़बड़ी हो रही है, यह बात हास्यास्पद है। यह हास्यास्पद इसलिए है कि उस इलाके में कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। महोदय, ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट में जो कानून है, उस में दूसरा आदमी दखल नहीं कर सकता। तो जमीन उनकी है और जिनकी है, वे वहीं पर खेती करेंगे। हो सकता है कि आज बाजार में कहीं कोई युद्ध होता हो, तो बात दूसरी है, किन्तु कार्बी आंगलां के इस इलाके में और नार्थ कछार के इलाके में सिर्फ अदरक की खेती को लेकर इतने लोग मारे जाएं, यह हास्यास्पद लगता है। मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि आप कृपया हमारी मांगों पर गौर फरमाते हुए सदन को बताने की कृपा करें। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Ms. Pramila Bohidar, you have five minutes.

Ms. PRAMILA BOHIDAR (Orissa) : Sir, for various reasons, Assam remains a sensitive State. Infiltration from across the border is one of the major problems being faced by the State.

In addition, ethnic disturbance is also continuing in some parts. This is being aggravated by some divisive elements and extremist organizations.

The recent massacre of innocent people, including women and children, in the Karbi Anglong district is a disturbing trend. This is not a social or ethnic issue alone. Neither the Central Government nor the State Government has taken enough steps to solve this problem.

I would like to suggest that an integrated, socio-economic approach is required to protect the small minority tribes and to maintain peace and harmony. The Centre should come out with a clear agenda and plan on this. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Thank you for being so brief. Shri Silvis, not present. Shri Robert Kharshiing-, not present. Now, Mr. Minister. *...(Interruptions)...* Yes, there are other names too. Shri Dwijendra Nath Sharmah.

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH (Assam): Mr. Vice- Chiarman Sir, my esteemed colleague, Mr. Ahluwalia, has explained about the situation prevailing in the tribal areas of Assam, particularly, in the districts of Karbi Anglong and N.C. Hills. The incidents that happened recently in Karbi Anglong and N.C. Hills were very sad. But, I do not agree with all the facts that Mr. Ahluwalia has given here.

Sir, Karbi Anglong, I think, is the biggest district in India and it is a hill district. The N.C. Hill is also a hill district of Assam. Though there are other tribes inhabiting the Karbi Anglong and N.C. Hills, the Karbis are the main inhabitants of Karbi Anglong district, while Dimasas are the main inhabitants of the N.C. Hills, North Cachar Hill district. There are two extremist outfits. One is the UPDS, that is, the United People's Democratic Solidarity in Karbi Anglong, and the other is the Dimasa Halam Daogal, that is, DHD in the N.C. Hills.

The hon. Home Minister has already given a statement that both the groups have surrendered and there is ceasefire, and they should have been in the camps. But what happened recently on 26.9.2005? Three persons were killed near Karbi Anglong. They belonged to Dimasa community. They were in an auto-rickshaw-one was auto driver and the other was passenger. They were Dimasa people. After killing them, they were brought to Karbi areas where their dead bodies were kept. Then Karbi people agitated over the death of these people. They also started killing. After two or three days, they killed five people. I am sorry to mention that in this clash both the communities have lost about 104 valuable lives in Karbi Anglong and N.C.

Hill. I have to mention here that Kabri Anglong villages consist of 15 or 20 families in remote areas. It is the biggest district of Assam, not only of Assam but it is the biggest district of the country. These people live in small places in hill tops. Out of fear, most of these families have left their houses. They have gone to other places to take shelter. By this time, 50,000 people, as Mr. Ahluwalia has rightly said, have left their houses. These vacant houses were burnt in different places in Karbi Anglong and N.C. Hill also. Now, Sir, at the moment, 19,500 people are in 39 relief camps-2,000 people are in 7relief camps of N.C. Hill and 16,000 in 10 camps of Naigaon. As the hon. Home Minister has mentioned, suddenly one bus was attacked and about 40 passengers were killed. After that also, about 1,385 vacant houses were burnt by miscreants-here vacant houses mean, houses left by people in villages. It was difficult to identify who burnt those houses. Till now, the Government of Assam has taken a lot of measures. About 266 persons have been arrested in this connection. The Minister of State, Home immediately visited there. He was camping there; he was staying there. The Chief Minister also visited the spot on 10th of October. He started discussion with both the groups-Karbi and Dimasa. He called them to Dispur and started discussion saying that this type of incident should be stopped and let peace prevail there. (*Time bell).* Both these groups were not agreeing to sit together. So, the Chief Minister sat with them separately and discussed with them separately. On. 18.10.2005, the Chief Minister discussed with both the groups. *...(interruptions)...* Sir, I will take some more time because *...(Interruptions)..*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Your time is already over. But you can take one or two minutes. *..(Interruptions)...* Try to conclude it in one or two minutes. *...(Interruptions)...*

SHRI DWIJENDRANATH SHARMAH: Again on 26.10.2005, the Chief Minister discussed the issue with the apex bodies of Karbi Anglong and Dimasas. On 21.10.2005, hon. Speaker of Assam Assembly headed an all-party delegation and they also visited the Karbi Anglong. Sir, Mr. Ahluwalia has said that no inquiry has been ordered, but the Assam Government has ordered an inquiry under Justice PC. Phukan. It is a one-man inquiry committee.

SHRI S.S. AHLUWALIA: He is a retired Judge. I am asking for a sitting High Court Judge. This inquiry too has been ordered after our demand.

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: He is a retired Judge. Then, what the Assam Chief Minister is trying to do is to bring both the groups, namely, DHD and Dimasas and Karbis, to negotiating table and he is trying his best to discuss the matter and come to a solution. Now, Sir, all these actions have been taken by the Assam Government and now situation is improving and we believe that normalcy will return immediately both in Karbi Anglong and N.C. Hills. But, there are certain suggestions. Mr. Ahiuwalia has rightly said that so many tribal organisations, particularly *Janjati Peeth* and Cultural Protection for Assam have met hon. Home Minister and submitted a memorandum and they have given some suggestions in their memorandum that certain steps should be taken to defuse that situation and main problem in Karbi Anglong and N.C. Hills is the backwardness of their people. They are educationally and economically backward. That is the main reason, as I understand, of this quarrel. Land dispute is also the main reason of these incidents. Then, another point, as he has rightly said, is this Greater Nagaland-I don't like to elaborate that point because it is relevant to some other issue-which includes Karbi Anglong and....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): Please, conclude.

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: That is also one of the reasons of these incidents. So, Sir, I urge upon the Government and all the parties that some steps should be taken for economic development of Karbi people and Dimasa people. I would like to urge upon the Home Minister that those people, who have been affected by these violent incidents, those who have lost their houses in Karbi Anglong and N.C. Hills, should be given a package by the Government of India so that their rehabilitation and reconstruction of their houses can be taken up urgently and relief should continue for some time more so that these people, after getting confidence from the Administration, can go back to their villages. Security measures should also be continued for some time. The Government of India has already sent some Forces and at the moment, I am sure that the situation is improving. But, steps are necessary to improve the living condition and economic condition of Karbi people and Dimasa people. I urge upon the Government of India that such steps should be taken and both the extremist groups, DHD and Karbis group, should be invited for discussion by the hon. Home Minister after which, I think, situation will improve. With these words, I thank you, Sir, for giving me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) You have taken more time.

SHRI S. S. AHLUWALIA: He has supported all my demands, still he says that he disagrees with me.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Shri Matilal Sarkar. Please complete within five minutes.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, it is a very painstaking matter that we are going to discuss here. I have some points to seek clarifications on the statement given by the hon. Home Minister. These incidents may occur, as occurred around the autorickshaw that has been described by hon. Member Mr. Sharmah. But my question is: basing on that incident, two militant groups, UPDS and DHD took lead in killing the innocent persons. What I understand is that two groups are maintaining ceasefire. But when the ceasefire was going on, how clould they take to arms. Why were they not disarmed, why were they not asked to give up arms when the ceasefire was going on? Because of their arms, they could indulge in such type of killings. This is my first question.

Sir, my second point is about the intervention by the Government. These disturbances continued for weeks together. The incident occurred in September and it continued for weeks together. How could it continue for such a long time? Why could not timely intervention take place and why were steps not taken to curb these disturbances? This is my second point.

Sir, my third point is that it is a fact that the Karbi Anglong area is dominated by the *Karbis* and N C Hills is dominated by the *Dimasas.* But on one point both *Karbis* and *Dimasas* are united. They are united in demanding Autonomous Statehood and that is a democratic movement. That is not a movement with arms. Whether Autonomous Statehood is permissible or not, whether we agree to it or not, is a different matter. But it is a fact that both the communities are united in putting forth their demand.

But the extremists groups of both these communities are disrupting their unity. That point should be taken into consideration. They are disrupting peace, they are disrupting unity and they are disrupting integrity. These extremists groups are on the way to disintegration but whereas the other side of the picture is that both the communities and all the

communities in that region are fighting for Autonomous Statehood. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what steps the Central Government is going to take with regard to their demands. If not Autonomous Statehood, at least, in order to increase the autonomy of their rights, some steps should be taken so that this feeling of frustration may be diminished.

Sir, my fourth point is that the peace initiative is very weak. Ethnic crisis are very often there. Only if peace initiatives are taken all over the disturbed area, when these ethnic groups are allowed to sit together, and, their grievances are heard, their problems will be sorted out, and, peace initiatives can be maintained in that area. But, so far what I learnt was that this peace initiative is very weak on the part of the Government. It is true that local artistes, persons on the cultural front, have come forward to normalise the situation.

They are taking initiative for bringing normalcy in the area. But this is not sufficient. This initiative, this encouragement, should come from the Government first. The Government should first come forward to see how the peace initiative can be undertaken. *{Time-bell)*

My fifth point is that still people are living in relief camps. Proper steps are not being taken to rehabilitate them. They are not allowed to live in their own homes; still they are living in relief camps. When will they be brought home or in the safe custody, so that they may live their normal lives? The economic condition of those ethnic people should be taken into consideration. The development works should usher in all over the areas, so that their fear of deprivation may come to an end. Without launching such a drive, no initiative of peace can last longer. Thank you, Sir.

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल)**:** धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, आपका यह वक्तव्य मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है और आपके इस वक्तव्य तक ही मैं अपना स्पष्टीकरण सीमित रखना चाहूंगी। इसमें से तीन बिन्दु ऐसे निकलते हैं जिसमें से मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी और कुछ आपसे पूछना भी चाहूंगी। गृह मंत्री जी, आपने इसके पैरा-2 में सदन को यह सूचित करते हुए बताया कि असम के कार्बी आंगलांग जिले में कर्बीज और उसके साथ उत्तरी कछार हिल्स जिला में दिमासा रहते हैं, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है विभिन्न जनजातियों के बीच तनाव एंव प्रतिस्पर्द्धा पैदा हो गई है। गृह मंत्री जी, एक तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि

1.00 P.M.

यह स्थिति का सही विश्लेषण नहीं है। यह ठीक है असम में और वैसे भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ जनजातियों के बीच में तनाव रहा है, जैसे नागाज और महार्स के बीच में संघर्ष हुआ है, नागाज और कुकीज के बीच में पूर्व में संघर्ष हुआ है। लेकिन जिन जनजातियों के बीच में इस समय यह लड़ाई हो रही है यानी कार्बी और दिमासा उनका आज तक का परम्परागत इतिहास कभी भी संघर्ष का नहीं रहा। वे दोनों जातियां आपस में बहुत ही प्यार से रहती है। उपसभाध्यक्ष जी, आप हैरान होंगे, अगर यह तथ्य मैं सदन को बताऊं कि इसमें से कार्बीज अपने को भीम का वंशज बतलाते हैं और दिमासा अपने आपको सुग्रीव का वंशज बतलाते हैं। सुग्रीव रामायण का चरित्र है और भीम महाभारत का चरित्र है। ये दोनों अपनी वंशावली रामयण और महाभारत काल से लेकर आते हैं और उन हजारों वर्षों में कभी भी इनमें संघर्ष नहीं हुआ, कभी इनमें तनाव क्या मनमुटाव तक नहीं हुआ। बहुत ही प्यार से ये दोनों जनजातियां आपस में रहती आई हैं। इसीलिए मैंने जो कहा कि आपने यह लिखा है कि इनमें तनाव और प्रतिस्पद्धा पैदा हो गई है यह च्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तनाव और प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस कोशिश के बावजूद अभी वह तनाव पैदा नहीं हुआ। कार्बीज यहां आए थे, दिमासा का भी प्रतिनिधिमंडल यहां आया था। आपसे भी मिला था और हम लोगों से भी मिला था और अहलुवालिया जी ने ठीक कहा कि एक जगह तो जोइंटली उहोंने कहा था कि हम नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ना चाहते भी नहीं हैं और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में तनाव पैदा करने के लिए यहां तक किया जा रहा है कि जब दिमासा मारे जाते हैं तो कार्बीस के घर के आगे उनकी लाश छोड़ दी जाती है और जब कार्बीज मारे जाते हैं तो दिमासा के आगे डाल देते हैं ताकि कर्बी यह मान लें कि हमें दिमासा मार रहे हैं। मगर उनका बुद्धि और विवेक आज भी इतना जागरूक है कि वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वे यह कहते हैं कि नहीं, हमारे बीच में यहप्यार बने रहना चाहिए, हम एक दूसरे को नहीं मारना चाहते, हमारा हजारों वर्षों का परम्परागत प्यार का इतिहास है, इसे बनाए रहने दीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आप यह विश्लेषण करेंगे कि प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने की कोशिश और साजिश के बावजूद वह प्रतिस्पर्द्धा पैदा नहीं हुई हैं और इसीलिए हमें वह उपाय करना चाहिए कि वह प्रतिस्पर्द्धा पैदा न हो और बार बार जिसको तीसरी शक्ति कह रहे थे अहलुवालिया जी.....। हम इसका पता लगायें कि कौन लोग हैं जो इनमें प्रतिस्पर्द्धा पैता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगी गृह मंत्री जी कि सारे प्रलोभनों के बावजूद ये दोनों जनजातियां धर्मान्तरण से भी बची रही है, इन्होंने कभी अपने आपको धर्मान्तरित नहीं होने दिया। इसीलिए जरा पता लगाइए कि वे कौन ताकतें हैं, जो इन दोनों को भिड़ा करके अपना स्वार्थ सीधा करना चाहती है। यह मेरा पहला सवाल है।

मेरा दूसरा बिंदु है जिसके बारे में आपने कहा है। ऐसा आशंका है उस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाने के लिए कुछ खास जनजातियों के उग्रवादी ग्रुपों ने इन हिंसक गतिविधियों को उकसाने का

काम किया। गृह मंत्री जी, यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। ये जो उग्रवादी ग्रुप है, इनको हथियार कौन पहुचा रहा है, क्या आपने इसकी जांच करने की कोशिश की? मैं आज सदन में आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप जरा पता तो लगाइए कि इनको हथियार कौन पहुंचा रहा है और मैं यह मानती हूं कि जब आप पता लगायेंगे, तो बहुत आश्चर्जनक, चौंकाने वलाले तथ्य आपके सामने आयेंगे। मेरा पास कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन मैं सार्वजनिक तौर पर, सदन में उनका खुलासा नहीं करना चाहती हूं। अगर आप चाहेंगे, तो आपसे मिलकर, उसकी जानकारी मैं दे दूंगी। लेकिन हो सकता है, चूंकि हम विपक्ष में बैठे हैं, आप यह कहें कि हमारी जानकारी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इसलिए मेरा आपको एक सुझाव है। आप सर्वदलीय पांच जनों का एक प्रतिनिधि मंडल कार्बी आंगलांग भेजिए, फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर भेजिए। आप उनसे कहिए कि वे तथ्यों का पता लगाकर आयें और फिर वे आपको आकर के जानकारी देंगे कि इन उग्रवादी ग्रुपों को हथियार कहां से मिल रहे हैं। वे कौन लोग हैं जो आज भी कर्बीज औरह दिमासा के बीच में इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पांच लोगों का प्रतिनिधि मंडल फैक्ट, फाइंडिंग मिशन पर भेजेंगे, तो वे आपके पास आकर अपने अनुभव शेयर करेंगे। जो जानकारी आज आपको केवल ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से मिल रही है, केवल अधिकारियों के माध्यम से मिल रही है, उन दोनों में आप तालमेल बैठायेंगे, तब आपको सच्चाई का पता लगेगा। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांच लोगों का एक शिष्ट मंडल, सभी दलों का मिला-जुला आप वहां फैक्ट, फाइंडिंग मिशन पर भेजिये।

तीसरी बात मुझे एक छोटी सी कहनी है। आपने आखिर में पैरा सात में कहा कि स्थिति की बारीकी से मानिटरिंग की जा रही है, इस क्षेत्र में अतिरिक्त केन्द्रीय पुलिस बलों और सेना यूनिटों की तैनाती जारी है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वहां स्थिति ऐसी नहीं है जो केवल पुलिस और सेना के बल पर ठीक की जा सके। पुलिस और सेना बल की अपनी एक भूमिका होती है। दो संघर्षरत गुटों के बीच में जाकर वे बीच-बचाव कर सकते है, अलग कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वहां समस्या है पारस्परिक खोए हुए विश्वास को वापस लाने की, वहां समस्या है खोए हुए प्यार को वापस जगाने की और इसमें सेना और पुलिस कोई भूमिका नहीं निभा सकती। आप जरूर सेना और पुलिस को भेजिए, लेकिन यह जो बारीकी से मानिटरिंग की जा रही है, यह एक रूटीन वाक्य होता है जिससे कोई भी वक्तव्य समाप्त होता है। लेकिन वहां की जो समस्या है, वह समस्या कहीं ज्यादा बड़ी है। गृह मंत्री जी, असम की इस तरह की जनजातियां हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूर्वोत्तर की किसी भी समस्या को जस्ट अनादर प्राब्लम कहकर हम नहीं कर सकते, वहां रूटीन वाक्यों से हम वक्तव्य समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वहां कुछ और करने की जरुरत है। वे जनजातियां हमारी अपनी जातियां हैं, हमारे साथ जुड़ी है, देश के साथ जुड़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि

इतने संघर्ष के बावदूद, सौ-डेढ़ सौ लोगों के मरने के बावजूद हमारे साथ बने रहना चाहती है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, कुछ और करके उस खोए हुए प्यार और उस खेए हुए विश्वास को वापस लाना चाहिए।

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Sir, thank you very much for allowing me to take part in this discussion. Sir, this is about the ethnic violence that took place in two districts of Assam. The hon. Member from the Opposition, Shrimati Sushma Swaraj, has said that the reason for violence has to be seen, and I agree with the viewpoint expressed by her. There is a history of these two Districts of Assam that the situation has always remained peaceful there; there was no hatred between the two communities; both the Government in Assam and the Government at the Centre, for a long time, have been taking care of them, and there were no incidents of violence against each other. The way the sudden violence has taken place, it apears that there are certain elements who are trying to create differences between the two communities and take political mileage out of that. They are against the State Government; they are also against the Autonomous Council that is taking care of these communities. The Dimaches and the Karbis have been living together. There is a corridor in the North Cachar Hills for the Dimaches. There is nothing wrong as such. It is very surprising to know that there are certain elements who have taken the law in their hands to incite one community against the other community. There is no failure on the part of the State Government; there is no failure on the part of the local self-Government. As you know, Sir, in the hill areas, it is typographically very difficult to understand where the anti-social elements are working. The same situation is prevailing in Jammu & Kashmir. The Central Government and the Jammu & Kashmir Government are trying their best to stop clashes among the people. Despite that, the incidents of violence are happening. To our utter surprise, though the State Government has always been very alert and has taken all care, the incidents of violence are occurring. The Opposition Members also know that after the sudden eruption of these clashes between the two communities, the Government of Assam took all care, took all measures to curb the violence and bring peace in the State. Now, the situation in the State is peaceful. The State Government has also taken care of it. We are grateful to the Central Government is taking care of the situation. The State Government has also taken care of it. We are grateful to the Central Government for

taking care of the people and also for helping the State Government to bring the situation under control. There is a political propaganda made against the State Government that it has been instrumental in creating problems. What is the interest of the State Government in allowing the two communities to fight against each other? The State Government is in no way responsible for the incidents of violence that took place in the hill areas. So, our Government is still trying to find out the reason and how it has taken place. And there are reasons which cannot be told here because it is the concern of the Home Ministry; they will take care of it. So my suggestion is that there is no need for sending an all-party delegation there to find out the reasons when things are cooling down. Sending the delegation will again create some sort of excitement among the people; that will not at all help in controlling the situation. I oppose what Madam Sushma Swaraj was saying. We are not going to help the people living in the hill areas by just sending the delegation there. The people are trying to come closer to each other; they will think that there is a third party which is trying to create problems there and take political mileage. Therefore, it is very, very dangerous to ask for a Parliamentary Delegation to go there and find out the cause. Now, the people living in the hill areas of Assam are quite silent. They are trying to settle down. They are trying to have a post mortem of that, why the people have fought, causing so much loss to the life. There was a great loss to their State and there was also a great loss to their Districts. It will be a problem for both the Government, the State and the Central Government. Sir, my submission is, since the situation is now improving, no Parliamentary Delegation should be sent there; that will, rather, excite the people and will again create the problem. With these words, I oppose the visit of an all-party delegation to the hill areas for finding out the cause of such incidents.

श्रीमती शिवराज वी.पाटिल: श्रीमन्, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर अहलुवालिया जी ने ध्यान आकर्षित किया है और यहां पर अनेक सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। असल में इस विषय पर लेजिस्लेटिव असेंम्बली में चर्चा करने के बाद तुरंत उसके ऊपर उपाय किए जा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी बताया जा सकता है, परंतु वहां पर जो घटना हुई है, वह बहुत बड़ी घटना है और उसकी ओर सारे देश का ध्यान आकर्षित हुआ है, इसलिए यहां पर चर्चा करना कोई गलत बात नहीं होगी, इसी उद्देश्य से इसकी चर्चा यहां हम लोगों ने की है। जो भी सुझाव इस सदन में दिए गए हैं, वे सुझाव हमने नोट किए हैं और जिन सुझावों

पर हम यहां से कदम उठा सकते हैं, उन सुझावों पर हम कदम उठाएंगे और जो सुझाव वहां की प्रांतीय सरकार को भेजने चाहिए, वे उनको हमें जरूर भेज देंगे और उनको भी कहेंगे कि आप उसमें जो कर सकते हैं, वह जरूर करें। एक सुझाव ऐसा था कि इनक्वायरी कमीशन का गठन किआ जाए। यहां पर अभी बताया गया कि इनक्वायरी कमीशन तो बैठाया है और हाई कोर्ट के जज के द्वारा उसकी जांच-पड़ताल हो रही है। यह पूछा गया ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस.अहलुवालिया: यह सही नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह सही नहीं है।...

That is not correct. What is said is not correct. You can get this information from the State. (*Interruptions)...*

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, he is right. Mr. Phukan is a retired Judge. *...(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the point is that the people of Karbi Anglong are demanding a CBI inquiry or an inquiry by a siting High Court Judge. *...(Interruptions)...*

SHRI SHIVRAJ V. PAUL: That may be true.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Now, let the Minister reply. Mr. Ahluwalia, please. *...(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: So many people were killed. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No. The hon. Minister will take care of it. *...(Interruptions)...* Don't worry. He will reply to it.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it has to be understood that an inquiry has been constituted and a retired High Court Judge is inquiring into it... *(Interruptions)...* It is not always possible to get a sitting High Court judge to inquire into the matter.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): What the hon. Member says is that it should be announced. *...(Interruptions)...* Mr. Ahluwalia, please don't repeat. *...(Interruptions)...*

SHRI SHIVRAJ V PATIL: That is his demand. What I am saying is that the State Government has continued an inquiry which is being done by a retired High Court Judge and this is being done *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No. Let the Minister reply *...(Interruptions)...* Mr. Ahluwalia, this is not the way. *...(Interruptions)...* Please.

SHRI S.S. AHLUWALIA: The Home Minister has no information *....(Interruptions)...* It was only announced. *...(Interruptions)...* It was not constituted.... *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Ahluwalia, please take your seat. ... *(Interruptions)...* Please take your seat. *...(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is the reason why a delegation came and met the Home Minister. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No. If there is any factual mistake in the hon. Minister's statement, there is a rule for correction....*(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is wrong information *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): There is a rule in the rule in the rule book for correction *...(Interruptions)...* You know that. *...(Interruptions)...* Don't interrupt like this. *...(Interruptions)...* Please don't interrupt. *...(Interruptions)...* Nobody will interrupt. *...(Interruptions)...*

SHRI SHIVRAJ V PATIL: Sir, I will give adequate time to Mr. Ahluwalia to say what he wants to say. *...(Interruptions)...* I will give him time. But I would request him not to interrupt me. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Okay. Now, Mr. Ahluwalia, after the Minister's reply, I will allow you, if you want to seek any clarifications. Don't interrupt, please.

SHRI SHIVRAJ V PATIL: Sir, the facts which have come before us are these. One hon. Member, who comes from that area, said very responsibly on the floor of the House that an inquiry had been constituted and it was going to be headed by a retired High Court Judge. Mr. Ahluwalia said, "Yes, you have done it after we made a demand". Yet he said, "You have appointed a retired Judge and we are asking for a sitting Judge". Sitting judges are not available. You should understand that the number of judges in High Courts and in the Supreme Court is not that much which should have been there. That is why it is not always possible to

get a sitting judge because a lot of cases are pending in courts. My information is that an inquiry has been announced. That has been announced means what? It means the formalities, which have to be completed, will be completed. If it has been announced, it is not going to remain unconstituted or it is not going to work like that. Even after that, if what you are saying is correct, we will request the State Government to complete the formalities immediately and start the work.

The point I am trying to make is, what you were asking for has already been given, except the fact that the retired judge will be heading the inquiry or the commission, not a sitting judge. That is the only difference. You have also said that this was done after you made the demand.

So far as compensation is concerned, the hon. Member has said that compensation has not been given. My information is that 12 families have received the compensation. The compensation has ben allowed to be given to the surviving members of the families who have lost their near and dear ones. But there are certain formalities which have to be completed like who should be given the compensation; otherwise, the compensation will be given by the Government and the person, who is not expected to receive that compensation, may grab that compensation and disappear. There are certain formalities which have been completed. It will be done. I would expect that the compensation, after completing the formalities, should be given without delay and it will be given. There is no difficulty on that. Now the Government of India also has given a certain amount of money to the State Government for helping them. It is a small amount of money. Nearly Rs. 6 crores have been given. But that amount has been kept at the disposal of the State Government for giving compensation. There was a suggestion that their houses should be reconstructed and given to them. I do think that if the houses have been burnt in large numbers, it would be necessary. The poor people should be given shelter. Some effective steps shall certainly be taken in this respect. It was stated that these two Tribes are not fighting with each other, झगडा नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। वे मेरे पास भी आए थे और दोनों ने भी बताया कि हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। दूसरे लोग झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करना जरुरी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यहां पर एक सवाल पूछा गया कि जो उनके पास हथियार थे, वे हथियार उनके पास से क्यों नहीं निकालकर लिए गए हैं? मेरे ख्याल से ग्राऊंड रूल्स भी हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है, तो सीजफायर के ग्राऊंड रूल्स

है। ये सीजफायर दोनों ग्रुप्स के लोगों में नहीं है, दोनों अलग-अलग ट्राइब्स के बीच में यह सीजफायर नहीं है। यह जो सीजफायर है, वह स्टेट गवर्नमेंट और मिलिटेंट ग्रुप्स के लोगों में है। सबसे अहम बात तो यह है कि वे हथियार लेकर कहीं नहीं घूमेंगे, वहां नहीं जाएंगे और हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, यह बात है। शायद इसीलिए हमको यह नजर आता है कि किसी को गोली मारकर खत्म नहीं किया गया है। वह दाव से मारा गया है, तलवार से मारा गया है, यह बात भी उसके अंदर नजर आती है। जो एक अहम बात हमारे सामने आ रही है, वह यह है कि नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में ये झगड़े बहुत होते हुए हमको नजर आते हैं। जब हम कहते हैं कि ट्राइब्स में झगड़े हो रहे हैं तो यह मानना कि उन लोगों में झगड़े हैं ही नहीं और वे बहुत प्यार से रहते थे। यह बात सही है और बहुत हत तक सही है, जो जंगल में हमारे भाई-बहन रहते हैं, वे इंसान से तो करते ही हैं साथ ही झाड़ से, फूल से और पंछी से और जानवरों से भी प्यार करते हैं। वे प्यार भरे होते हैं और प्यार करते ही हैं। यह बात भी सही है कि कुछ लोग वहां पर एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं और यह बात भी सही है कि कुछ लोग उनमें झगड़ा लगाना चाहते हैं। यह बात भी सही है कि झगड़ा लगाने वालों में हमारे यहां के भी कुछ लोग हो सकते हैं और बाहर के भी कुछ लोग हो सकते हैं। उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वाद करके दूसरों का नाम लेकर दूसरों को बदनाम करने की कोशिश में रहते हैं।

इन सारे हालात को सामने रखते हुए जो मौजू कदम हमको उठाना जरूरी है, वे उठाने चाहिए और ऐसी ही कोशिश स्टेट गर्वनमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से हो रही है। मगर एक बात सही है कि नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्राइब्ज के अंदर जो झगड़े हैं, वे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नागा और मैती में झगड़े हैं, कुकी और नागा में झगड़े हैं, दिमासा और कार्बी के बीच में झगड़े हैं, बोडो में झगड़े हैं, और ये झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या जड़ है- छोटा विचार और छोटा दिमाग। अगर देश के लेवल पर, हम धर्म के नाम पर झगड़ा करेंगे, तो उसका असर जाति को मानने वाले लोगों पर होगा। अगर हम जाति को लेकर झगड़ा करेंगे, तो sub-tribe के लोगों में झगड़ा होगा। ये झगड़े एक दिन में शुरू नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि बारूद का बाक्स लगाया है, match-box लगाकर उसको explode कर दिया गया। जब हम छोटे विचार को सालों तक लोगों के सामने रखते हैं, तो अहिस्ता आहिस्ता वह जहर बनकर, उनके दिमाग और उनके सोचने का एक अंग बन जाता है और उसी से बड़े-बड़े नेताओं की हत्या होती है और उसी से बड़ी बड़ी ट्राइब्ज के बीच में झगड़ा होता है, उसी से अनेक जातियों के लोगों में झगड़ा होता है, उसी से अनेक धर्मों के लोगों में झगड़ा होता है। इसकी जड़ छोटा मन है, छोटा विचार है और वह छोटा विचार न हो तो सारे झगड़े हल हो सकते हैं। इस पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि यहां पर बताया गया है कि सारा संसार हमारा घर है और हम उसके मेंबर हैं, ऐसा बताया गया है। छोटे मन वाले लोग, इस संसार को अपना घर नहीं मानते हैं, मगर कुछ लोग अपने धर्म के लोगों को अपना

मानते हैं, कुछ लोग अपनी जाति के लोगों को अपना मानते हैं, कुछ लोग अपनी ट्राइब के लोगों को अपना मानते हैं कुछ लोग sub-tribe के लोगों को अपना मानते हैं, कुछ लोग पड़ोसियों को अपना मानते हैं. फिर कुछ लोग अपने को ही अपना मानते हैं, आखिर में कुछ लोग अपने घर के लोगों को भी अपना नहीं मानते है, ऐसी हालत है जाती है। तो इसकी जड़ छोटे मन में है। अगर यह छोटा मन नष्ट हो जाए बहुत अच्छा होगा।

सुषमा जी ने जो कहा, वह बहुत सही बात है और होम मिनस्ट्री की तरफ से हम जो कार्यवाही कर सकते हैं, हम करेंगे। यह जो चीज हैं, यह पूरी सरकार को करनी पड़ेगी। सिर्फ सरकार के करने से नहीं चलेग़ा, समाज को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी यह हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। शिक्षा के माध्यम से, हमारी जो सही संस्कृति है, उसके माध्यम से और जो सांसारिक संस्कृति हैं, वैश्रिवक संस्कृति हैं, उसके माध्यम से यह काम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।

अंत में मैं इतना कहूंगा कि आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर हम यहां से जो कार्यवाही कर सकते हैं, वह हम जरूर करेगे और स्टेट गवर्नमेंट को हम कार्यवाही करने में मदद करेंगे। जब हम पुलिस की बात करते हैं, कही झगड़ा होने के बाद हमारे पास पहली डिमांड यह आती है कि 5 कंपनियां भेज दिजिए,2 बटालियनें भेज दिजिए, 4 बटालियनें भेज दिजिए। जब कहीं की घटना होती है, तो उसका उत्तर है वहां पुलिस ही संख्यां बढ़ा देना, मगर मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि हर स्टेट के पास बहुत पुलिस है। उस पुलिस का उपयोग होना चाहिए। एक-एक स्टेट के पास 70,000 पुलिस अफसर हैं, उनका deployment's अच्छे ढंग से होना जरूरी है। यह deployment's अनक अनक किसी को डराने और धमकाने के लिए नहीं है, मगर जो दुष्ट प्रवुत्ति के लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ही पुलिस है, उसका उपयोग करना जरूरी है और सही ढंग से करना जरूरी है। हम आशा करते है कि हम सब लोग मिलकर, केन्द्र की सरकार प्रांत की सरकार इस काम को करेंगे। और सभी पार्टियों के लोग इसमें मदद करेंगे। जो घटना हुई है,वह अत्यत दःखुद है। जिनके घर में घटना हुई, उनको हम अपनी तरफ से औऱ सदन की तरफ से संवेदना भेजना चाहेंगे औऱ उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी मदद हम कर सकते हैं, सरकार के नाते और समाज की ओर से वह मदद हम जरूर करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: गृह मंत्री जी, मैंने कहा था कि एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन वहां भेजिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल: ऐसा है कि आपने डेलीगेशन भेजने बारे में कहा था और कुछ दूसरे लोगों ने भी कहा था, लेकिन अभी हमको बताया गया है कि वहां के स्पीकर साहब ने एक डेलीगेशन Lead किया है और उसमें हर पार्टी के लोग थे वे वहां जाकर आएं है। जब वे कर रहे हैं तो बार-बार जेलीगेशन भेजना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इससे मदद के बजाय तकलीफ होगी।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उपसभापति, महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे सवालों के जवाब में कहा कि जस्टिस फुक्कन कमीशन वहां कंस्टीटयूट किया गया है मैं मंत्री महोदय, से बार-बार आग्रह करुंगा कि फुक्कन कमीशन की केवल घोषणा की गई है।

श्री शिवराज वी. पाटिल: तो वहीं मेंने कहा।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: वह जब तक कंस्टिटूयूट नहीं होती, जब तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पब्लिश नहीं होते, जब तक वे पब्लिश करके आम जनता की एफिडेविट की डिमांड पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक वह कंस्टिटयूट ही नहीं हुई। उन्होंने शुरूआत दिनों में सिर्फ अनाउंसमेंट की, मैं ने उसका उल्लेख किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार जो डेलिगेशन आपको भी मिला और मुझे भी मिला उनकी मांग थी कि either सीबीआई की या सिटिंग जज की इन्क्वायरी हो। यह अभी तक कांस्टिटयूट ही नहीं हुई है, यह सिर्फ घोषणा है।

दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि सिटिंग जज उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि किस तारीख को वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था और चीफ जस्टिस ने कहा कि जज उपलब्ध नहीं है। क्या आप बताने की कृपा करेंगे?

दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि सिर्फ 12 आदमियों को कंपेंसेशन दिया गया है। एक सौ से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 148 लोग मारे गए हैं और उनमें से सिर्फ 12 आदमियों को कंपेंसेशन मिला, तो कितने परसेंट लोगों को यह मिला? कई हजार घर जलाए गए हैं, उनमें से कितने घरों में रिहैबिलिटेशन का बन्दोबस्त और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे? यह 26 सितम्बर से चल रहा है और अभी तक न तो इन्क्वायरी कमीशन कंस्टिटयूट हुआ, न वहां पर कंपेंसेशन और रिहैबिलिटेशन का काम शुरु हुआ। ये लोग कैम्प से वापस गांव कब जाएंगे?

श्री शिवराज वी.पाटिल: श्रीमन, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि यह सब्जेक्ट इस सदन का, इस सरकार का नहीं होते हुए भी हमने इस पर चर्चा की, इसका जवाब भी दिया, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। असल में यह सब्जेक्ट लेजिस्लेटिव असेम्बली में आना चाहिए। इसके बाद कॉल अटेंशन मोशन का मतलब यह होता है कि स्टेटमेंट करने के बाद You can ask a question to elicit some information, अब यह सब हो रहा है। इसके बाद आपने जो कहा है, इसका जवाब मैं इस प्रकार से देना चाहूंगा कि जो अनाउंसमेंट हुआ है, उस अनाउंसमेंट पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। वह कार्रवाई अगर नहीं होगी, तो हम वह कार्रवाई करने के लिए सरकार को जरुर बताएंगे। इसके ऊपर आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

जहां तक कंपेंसेशन का सवाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 लाख रूपये कंपेंसेशन दिये जाते हैं, तो एक भाई, दूसरे भाई, इसके घर के लोग एक-दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और इसमें कहीं-कहीं कई जगहों पर बहुत झगड़ा भी हो जाता है। यह कोर्ट डिसाइड करता है कि किस आदमी के हाथ में यह कंपेंसशन देना चाहिए। नहीं तो, वह चला जाता है। पैसे की कमी नहीं है, इसके अन्दर ये फॉर्मेलेटिज पूरी करने की है।

आप कह रहे हैं कि आपको यह कैसे मालूम कि लोग हाजिर नहीं हैं। हमारे देश में क्या हालत है, यह हमें मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज कम हैं। हाई कोर्ट के कितने जज कम हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, यह हमें मालूम है। दूसरे केसेज में जब चीफ जस्टिस को पूछा जाता है, तो वे कहते हैं कि we are not able to spare our judges, इसलिए मैं ने यह आपको बताया, अन्यथा दूसरी की बात नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Thank you Mr. Minister. I would like to have the sense of the House now. We will take up the Central Sales Tax (Amendment) Bill, 2005 and, thereafter, the Special Mentions. *(Interruptions)* No, no. Let me assure you that after this Bill, Special Mentions will be taken up because the Finance Minister.... *(Interruptions)* Please cooperate. हो जाएगा। हो जाएगा ...(**व्यवधान**)... Now, Mr. Chidambaram.

GOVERNMENT BILLS

The Central Sales Tax (Amendment) Bill, 2005

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I move:-

> "That the Bill further to amend the Central Sales Tax Act, 1956, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I will take only a couple of minutes to introduce this Bill.

Sir, the Central Sales Tax is a tax levied on inter-State sale of goods and is collected by the State Government. Now, against the orders of the Assessing Officers, appeals are provided. In 2001, 2002 and 2003, the Act was amended to provide for an appellate authority at the Centre.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI) in the chair. Unfortunately, while amending the Act, appeal was provided against the orders of an assessing authority. Now, the intention was not to provide for appeal in Delhi against the order of every assessing authority in every